अध्यक्ष का संदेश...

वित्तीय वर्ष 2024 में, बड़ी वैश्विक चुनौतियों का मजबूती से सामना करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2% की दर से विकास किया. लगातार तीसरे वित्तीय वर्ष में भी 7% से अधिक की वृद्धि दर को बनाए रखते हुए भारत, विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक मंच पर आसीन हो गया है.

यह एक शानदार उपलब्धि है, विशेषकर तब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ते भू-राजनैतिक तनावों, कम होती किंतु लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति और धीमी (आर्थिक) गतिविधियों जैसी समस्याओं से घिरी हुई है. यह उपलब्धि भारत को नवोन्मेषों और अवसरों की संभावनाओं के एक केंद्र के रूप में रेखांकित करती है, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में और भी अधिक गतिशील रूप से योगदान करने के लिए तैयार है. पूंजी निर्माण पर भारत के निरंतर ध्यान ने विकास की गति को बढ़ाया है. सरकार आधारभूत संरचनाओं और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काफी खर्च कर रही है ताकि इनमें मौजूद रुकावटों को दूर किया जा सके.

नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना और कृषि में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है. पिछले दशकों में, नाबार्ड का ग्रामीण आधारभूत संरचना वित्तपोषण ₹8.2 लाख करोड़ की संचयी मंजूरी तक पहुंच गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान मंजूर ₹61,000 करोड़ की राशि शामिल है. हमारी प्रमुख निधि 'ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि' ने ग्रामीण परिदृश्य पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है. इस निधि की सहायता से 422.2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता, 5.6 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों तथा 14.1 लाख मीटर ग्रामीण पुलों का निर्माण हुआ और 3,096 करोड़ मानव श्रम दिवसों के गैर-आवर्ती रोजगार का सृजन हुआ.

भारत में सहकारी समितियाँ समतापरक विकास तथा आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने और मजबूत समुदायों के निर्माण में एक रूपांतरकारी भूमिका निभाती हैं. इनकी महत्ता को पहचानते हुए, नाबार्ड ने वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का मुख्य अध्याय सहकारी समितियों को समर्पित किया है.

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और ऋण आपूर्ति के लिए ग्रामीण ऋण संरचना महत्वपूर्ण है. नाबार्ड ने स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया है और ग्रामीण भारत में समावेशी वित्तीय और ऋण संरचना में योगदान दिया है. हम 5 वर्षों की अवधि में 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का डिजिटलीकरण करवा रहे हैं. डिजिटलीकरण के इन प्रयासों से लेन-देन की गति तेज़ होगी, भुगतान सेवाओं तक पहुँच बढ़ेगी और ग्रामीण हितधारकों के लिए पर्यवेक्षण सुगम होगा. 24 फरवरी 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 18,000 डिजिटलीकृत पैक्स का उद्घाटन किया गया है.

नाबार्ड, उभरती आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बना हुआ है और अपनी नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल बनाता रहा है. कृषि जोतों के औसत आकार में आ रही कमी कृषि के विविधीकरण और किसानों की आय अर्जन क्षमता के लिए चुनौती है. इसके समाधान के लिए, नाबार्ड ने 7,355 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्धन किया है जिनमें 25 लाख किसान सदस्य हैं, जिनमें से लगभग 82% लघु और सीमांत किसान हैं.

नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि के संवर्धन के लिए विकास के अनेक संधारणीय और समावेशी मॉडलों का प्रवर्तन कर रहा है. इनमें वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) विशेष है, जिसके तहत 1.44 करोड़ से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते खोले गए हैं और 77.4 लाख स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण किया गया है. इन समूहों की कुल जमाराशि ₹65,089.2 करोड़ और उन पर कुल बकाया राशि ₹2.59 लाख करोड़ है.

जलवायु परिवर्तन कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए बड़े जोखिम उत्पन्न करता है. नाबार्ड जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनीयता प्रदान करने और संधारणीय ग्रामीण विकास को संवर्धित करने के माध्यम से आजीविका को सुरक्षित करने के श्रेष्ठ प्रयास कर रहा है. तीन महत्वपूर्ण जलवायु वित्तपोषण निधियों के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता इकाई (एनआईई) के रूप में हमने ₹1,971.50 करोड़ की 40 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है. नाबार्ड ने निवेशों की प्राथमिकता तय करने और हरित पोर्टफोलियो के लिए संसाधन संग्रहण हेतु एक हरित वर्गीकरण भी विकसित किया है जिससे उसके विकास और व्यवसाय पोर्टफोलियो को वर्गीकृत किया जा सकता है.

मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नाबार्ड के तुलन-पत्र का आकार वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 13.6% की वृद्धि दर के साथ 31 मार्च 2024 को ₹9.1 लाख करोड़ तक पहुँच गया. नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत के पहले एएए रेटेड रुपये में अंकित सामाजिक बॉण्ड के माध्यम से ₹1,040.5 करोड़ संग्रहित किए हैं, जिससे निवेशों को सामाजिक प्रभाव के साथ जोड़ा जा सके. नाबार्ड के सामाजिक बॉण्डों के माध्यम से निवेशक, सभी के लिए एक अधिक न्यायसंगत और संधारणीय भविष्य के निर्माण में योगदान कर सकते हैं.

नाबार्ड का भावी विज़न, 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हमारी पंचवर्षीय रणनीतिक योजना 'प्रगति 1.0' और अपनी आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुन:स्थापन की हमारी प्रक्रिया 'उन्नति' में समाहित है. हम साझेदारियों, नवोन्मेषी समाधानों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से सार्थक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं. अपने हितधारकों के साथ मिलकर, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं जिसमें हर ग्रामीण परिवार खुशहाल होगा और संधारणीय समृद्धि में योगदान दे रहा होगा.

मैं अपने हितधारकों, भागीदारों और नाबार्ड की समर्पित टीम के अटूट सहयोग और प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ. आइए हम सब मिलकर ग्रामीण भारत को मजबूती और समृद्धि की ओर ले चलें.

शाजी के. वी.
अध्यक्ष